शहर बनेगा नान लेदर फुटवियर का हब, खुलेंगे नए अवसर

कैबिनेट में उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नान लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 को दी गई स्वीकृति, उत्साहित हुए कारोबारी

जागरण संवाददाता, कानपुर : कैबिनेट में उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नान लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 को दी गई स्वीकृति से चमड़ा कारोबारी उत्साहित हैं। उनके मुताबिक इसे ठीक से लागू कर दिया गया तो अगले पांच वर्ष में शहर वियतनाम की तरह नान लेदर फुटवियर का हब बन जाएगा। यहां लेदर के साथ नान लेदर फुटवियर के साथ उससे जुड़ी तमाम इकाइयों को भी लगाया जाएगा, जिससे देश के साथ विदेश में भी कारोबार बढ़ेगा। कारोबारियों का कहना है कि अभी 6,500 करोड़ रुपये का हर वर्ष निर्यात होता है। इनके जरिये आने वाले समय में इसमें काफी वृद्धि होगी। हालांकि कारोबारियों का यह भी मानना है कि फुटवियर पार्क के साथ ही टेनरी को भी बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यहां टेनरी में जितना चमड़ा बनता है, उससे ज्यादा चमड़ा तो पहले से मौजूद फुटवियर उद्योग को चाहिए होता है, जिसकी वजह से चमड़ा आयात करना पड़ता है।

शहर और उन्नाव में इस समय करीब तीन सौ टेनरियां हैं। करीब इतनी ही फुटवियर इकाइयां हैं। प्रदेश सरकार ने कानपुर में 300 एकड़ में फुटवियर पार्क लगाने की बात कही है। इससे जूता उद्योग और तेजी से बढ़ेगा। चर्म उत्पादों के निर्माताओं को कहना है कि कानपुर पहले से ही चर्म उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। इससे नान लेदर के भी अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही एसेसरीज की इकाइयां भी यहां स्थापित होंगी। इसमें सोल, लेस, लाइनिंग, मेटल फिटिंग की भी इकाइयां यहां बनेंगी।

इसके होने से एक पूरा माहौल ही बदल जाएगा। दूसरी ओर टेनरियों को भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। चर्म उत्पाद निर्माताओं के मुताबिक पहले ही चमड़े की कमी है और बाहर से चमड़ा आयात करना पड़ रहा है क्योंकि टेनरियां पूरी क्षमता पर चल रही हैं और उनका चमड़ा यहां की निर्माता इकाइयों को कम पड़ रहा है।

टेनरी में चर्म उत्पाद बनाता कर्मी ● उद्यमी

> टेनरियों को भी बढ़ाने से जो फुटवियर पार्क बनेगा, उसे यहीं से चमड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर चमड़े का आयात करना पड़ा तो जो उत्पाद बनेंगे, उनकी कीमत बढ़ जाएगी। इसकी वजह से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे।
>
> **अशरफ रिजवान**, टेनरी संचालक व फुटवियर निर्माता

> इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे दूसरे देशों की कंपनियां भी आएंगे और ज्वाइंट वेंचर में नई इकाइयां खुल सकेंगी। इसके साथ ही नान लेदर इकाइयां शुरू होने से पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। अगले पांच वर्ष में इसकी स्थिति बदली हुई होगी।
>
> **यादवेन्द्र सचान**, फुटवियर व चर्म उत्पाद निर्माता

> ऐसे मौके पर जब अमेरिका से टैरिफ का विवाद चल रहा है, राज्य सरकार बिल्कुल सही समय यह योजना लाई है। रूस नान लेदर का बड़ा मार्केट है। इससे नान लेदर के लिए अवसर बढ़ेंगे। योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देने की बात है।
>
> **असद इराकी**, रीजनल वेयरमैन, चर्म निर्यात परिषद

उद्यमियों को मिलेंगे सस्ते भूखंड, तलाशा जाएगा लैंड बैंक

जागरण संवाददाता, कानपुर : औद्योगिक इकाइयां लगाकर देश के विकास में अपना हाथ बंटाने का सपना देख रहे युवाओं को अब सस्ती दर पर भूखंड मिल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने जो नीति तैयार की है, उससे उनकी पूरी पूंजी जमीन पर ही नहीं लगेगी। बड़ी संख्या में उद्यमियों को अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने का मौका मिलेगा। उद्यमियों के मुताबिक शहर में और कहीं तो जगह नहीं है लेकिन रिंग रोड के आसपास इसके लिए लैंड बैंक तलाशा जा सकता है।

रिंग रोड के आसपास भूमि तलाशी जाएगी, देश के विकास में अपना हाथ बंटाने का सपना देख रहे युवाओं को अब सस्ती दर पर भूखंड मिल सकेंगे

उद्यमी यूपीसीडा के भूखंडों के फ्रीहोल्ड न होने को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। खासतौर पर आइआइए के पदाधिकारी तो पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से इसको लेकर आंदोलन भी चला रहे हैं। अब इस योजना में भूखंड और शेड अनिश्चितकाल के लिए पट्टे पर मिलेंगे। इसलिए इस योजना को लेकर उद्यमी उत्साहित दिख रहे हैं। एमएसएमई इकाइयों के विकास के लिए लाई जा रही इस योजना को लेकर आइआइए कानपुर चैप्टर के मंडल अध्यक्ष दिनेश बरासिया ने कहा कि कानपुर में लैंड बैंक ही नहीं है। इसके अलावा ढाई हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की जमीन यहां मिलना मुश्किल है लेकिन जो रिंग रोड बन रही है, उसके आसपास की जमीनों को उद्योगों को विकसित करने के लिए लैंड बैंक के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसलिए यहां इस योजना के विकसित होने की उम्मीद है। उनके मुताबिक अनिश्चितकालीन पट्टे की वजह से उद्यमियों को राहत मिलेगी। अभी तय समय के लिए पट्टे से उद्यमियों को संकट है। समय आने पर उनका उद्योग खत्म हो सकता है। हालांकि ई-नीलामी पर उन्होंने कहा कि इसकी वजह से छोटी एमएसएमई इकाइयों को भूखंड लेना मुश्किल होगा क्योंकि बड़ी कंपनियां ई-नीलामी में बड़ी बोली लगाकर भूखंड खरीद लेती हैं और छोटी इकाइयां उसे ले नहीं पातीं।